नवभारत टाइम्स

बुधवार, 5 फरवरी 2025

क्या एंट्रेंस टेस्ट सही से कर रहा छात्रों का मूल्यांकन

2018 में बड़े एंट्रेंस टेस्ट देने वाले थे 60 लाख, अब 1.20 करोड़, डिमांड-सप्लाई में गैप बढ़ा रहा कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता

Bhupender.Sharma@timesofindia.com

देश में कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? क्या एंट्रेंस टेस्ट का सिस्टम सही मायनों में छात्रों के सीखने का मूल्यांकन कर रहा है? एंट्रेंस टेस्ट देने वालों की संख्या पिछले छह वर्षों में ही दोगुनी हो गई है। पैरंट्स अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों की कोचिंग पर खर्च कर देते हैं, कर्ज लेकर भी कोचिंग करवाते हैं और उसके बाद भी जरूरी नहीं कि बच्चे को पसंद के कोर्स में दाखिला मिल जाए। डिमांड व सप्लाई में इतना बड़ा गैप है कि कोचिंग सेंटरों पर बढ़ती निर्भरता को रोका जाना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स को बढ़ावा दिया है, ऑनलाइन कोर्सेज का विकल्प भी दिया है लेकिन अभी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रणाली में बड़े सुधारों की जरूरत है।

भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं और आवेदकों की संख्या में बड़ा इजाफा: यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार ने कहा, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण छात्रों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। जेईई, नीट, सीयूईटी और यूजीसी-नेट जैसी परीक्षाओं में छात्रों की संख्या जो 2018 में 60 लाख थी, वो अब 1.20 करोड़ हो गई है। प्रतियोगिता के इस दौर में यह संख्या और बढ़ सकती है। हालांकि वर्तमान में परीक्षाओं में डिफिकल्टी लेवल के कारण देखने में आता है कि बहुत से छात्र कुछ न कुछ सवालों के जवाब नहीं देते हैं और क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं। इस ट्रेंड से यह चिंता पैदा होती है कि क्या ये प्रतियोगी परीक्षाएं वास्तव में छात्र के सीखने का मूल्यांकन करते हैं या केवल नॉलेज गैप को सामने ला रही हैं? कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता भी मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार है।

विशेषज्ञों की राय

'एंट्रेंस टेस्ट को 12वीं के स्तर जोड़ना चाहिए'

यूजीसी अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार का कहना है कि अब सीयूईटी जैसी परीक्षाओं को 12वीं के स्तर के साथ जोड़कर कोचिंग पर निर्भरता कम की जा रही है। उनका कहना है कि इस मूल समस्या का समाधान करने के लिए एक आदर्श टेस्टिंग मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें एक बड़े क्वेश्चन बैंक और एक कंप्यूटर-बेस्ड आधारित मकैनिज्म का उपयोग कर सकते हैं, जहां हर छात्र को एक यूनीक क्वेश्चन पेपर मिले। एग्जाम के विश्लेषण के आधार पर डिफिकल्टी लेवल तय हो। सरकार ने भी इस समस्या का समाधान करने के लिए कई पहलें की हैं। कठिनाई स्तर को बोर्ड परीक्षाओं के समान रखने से इस अंतर को पाटने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों को मजबूत करना, धोखाधड़ी को रोकने के लिए तकनीक के इस्तेमाल से, पेशेवर कर्मचारियों को परीक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने से काफी फायदा होगा।

एंट्रेंस टेस्ट में स्कूल करिकुलम के बीच बेमेल बढ़ा रहा है कोचिंग सेंटरों का मायाजाल

परीक्षाओं के पैटर्न की समीक्षा जरूरी

एम. एम. पब्लिक स्कूल- पीतमपुरा की प्रिंसिपल **रूमा** पाठक का कहना है कि कोचिंग सेंटरों पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए परीक्षाओं के पैटर्न की समीक्षा करना जरूरी है। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद नियमित रूप से मूल्यांकन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न और एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। डमी स्कूलों की एक समस्या सामने आई है, जिस पर अब सीबीएसई एक्शन भी ले रहा है। पैरंट्स को भी यह समझना जरूरी है कि बच्चे को केवल कोचिंग सेंटर भेजने से काम नहीं चलेगा। स्कूल का तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, स्कूल में बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और एंट्रेंस टेस्ट में बच्चे का विश्वास भी सफलता की बड़ी कुंजी होता है।

एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न जनरल क्यों नहीं हो सकता

गुजरात नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी- गांधीनगर के रजिस्ट्रार डॉ. नितिन मलिक ने कहा, जब तक डिमांड वाले कोर्सेज की सीटों में जरूरत के हिसाब से इजाफा नहीं होगा, तब तक कोचिंग पर निर्भरता कम नहीं होगी। उनका कहना है कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज के लिए सबसे ज्यादा कोचिंग ली जाती है जबकि हिंदी, संस्कृत जैसे कोर्सेज के लिए कोचिंग नहीं ली जाती। उनका कहना है कि जिस तरह से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से कुछ हद तक सीटें भी बढ़नी चाहिए। बहुविषयक अप्रोच को हर सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाए। मसलन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को दूसरे कोर्स के साथ लेने के मौके ज्यादा दिए जा सकते हैं। जब आप कहते हैं कि 12वीं में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, फिर भी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो उस हिसाब से जरूरी बदलाव भी लेकर आएं। एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस भी जनरल क्यों नहीं रखा जा सकता है। टेस्ट के लिए इतना टफ सिलेबस दे देते हैं कि कोचिंग मजबूरी हो जाती है।